जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 44 संख्याः 37 प्रभात बीकानेर, गुरुवार 1 सितम्बर, 2022 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 1.20 रू.

जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए अमेरिका में विंड टरबाइन्स लगाने की होड़ लगी हुई है पर यह व्यवस्था पश्चिमी अमेरिका के सबसे शानदार परभक्षी पक्षी गोल्डन ईगल के संरक्षण में बाधा बना रही है, जबकि यह प्रजाति पहले से ही घट रही है। यह टकराव वायोमिंग में सबसे ज्यादा है, जो कि गोल्डन ईगल का गढ़ है और यहां विंड फार्म्स भी बड़ी तादाद में हैं। विंड टरबाइन्स की संख्या जैसे-जैसे बढ़ रही है, वैज्ञानिकों का कहना है कि, टकराने के कारण होने वाली मौत से गोल्ड ईगल की संख्या कम हो सकती है। नैशनल ऑडबान सोसायटी के एक विश्लेषण के अनुसार, जलवायु संकट इससे भी ज्यादा बड़ा खतरा है। सर्वे में कहा गया है कि, बढ़ते तापमान की वजह से इस सदी अंत तक गोल्डन ईगल के प्रजनन क्षेत्र में 40 प्रतिशत से ज्यादा की कमी हो सकती है। अतः बदलती जलवायु और गर्मी को रोकने के लिए विंड एनर्जी का इस्तेमाल, इन दोनों के कारण गोल्डन ईगल की मुश्किलें दोगुनी हो गई हैं। विल्सन, वायोमिंग, के टैटॉन रैप्टर सैंटर के संरक्षण निदेशक ब्रायन बैंडरोसियन ने कहा कि, ''वायोमिंग में गोल्डन ईगल की आबादी बहुत अच्छी है पर इसका अर्थ यह नहीं कि इनकी आबादी को खतरा नहीं है। जैसे -जैसे हम यू.एस. में विंड डवलपमैंट बढ़ा रहे हैं, यह खतरा बढ़ रहा है।'' कई सौ फीट लंबे विंड टरबाइन के ब्लेड बहुत बड़ा खतरा हैं। इसके अलावा लैंड पॉइज़न, वाहनों से टक्कर और बिजली के तारों से करंट का खतरा भी है। गोल्डन ईगल की तुलना में बॉल्ड ईगल के संरक्षण में भारी सफलता मिली है। वर्ष 2009 के बाद से बॉल्ड ईगल की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। अभी इनकी आबादी 3.46 लाख है, इसकी तुलना में गोल्डन ईगल की आबादी मात्र 40,000 ही हैं। गोल्डन ईगल को रहने के लिए ज्यादा जगह की जरुरत होती है। फैडरल अधिकारियों ने कोशिश की है कि टरबाइन से होने वाली मौतों में कमी आए, लेकिन फिर भी, कार्बन उत्सर्जन करने वाले ईंधन के विकल्प, ''विंड पावर'' की ग्रोथ में कमी नहीं की जा रही है, क्योंकि यह राष्ट्रपति जो बाइडन के क्लाइमेट एजेंडा का प्रमुख हिस्सा भी है। बैंडरोसियन जैसे वैज्ञानिक भी मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए और अधिक विंड टरबाइन्स की ज़रुरत है। पर विशेषज्ञ ऐसे तरीके भी ढूंढ रहे हैं जिससे गोल्डन ईगल की बढ़ती मृत्युदर पर अंकुश लगाया जा सके।

भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की उड़ान जमीन पर उतर रही है?

अन्तर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी ''रॉयटर'' के नवीनतम सर्वे के अनुसार, वर्तमान तिमाही में ग्रोथ रेट घट कर आधी रह जायेगी, पिछली तिमाही की तुलना में

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 अगस्त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मानती हैं कि भारत के आर्थिक विकास की कहानी अबाधित है और बैंकर्स ने भी इसे लेकर आशावाद व्यक्त किया है, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के मोर्चे पर आत्मसंतुष्टि रखने के प्रति चेतावनी दी है।

रॉयटर न्यूज एजेंसी द्वारा अर्थशास्त्रियों पर किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत के इस वर्ष की अंतिम तिमाही में दो अंकों की मजबूत आर्थिक वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है, लेकिन उसके वर्तमान तिमाही में पिछली तिमाही की तुलना में आधा प्रदर्शन करने और वर्ष की समाप्ति तक और मंद होने की आशंका है क्योंकि ब्याज दरें बढ़ रही हैं।

एशिया की तीसरे नम्बर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बेरोजगारी और महंगाई के उच्च स्तरों से जूझ रही है, जो कि अब तक रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया (आर.बी.आई.) के टॉलरेंस बैण्ड के शीर्ष पर रही है और वर्ष 2022 की शेष अवधि में भी इसके ऐसा ही रहने की उम्मीद है।

- **वित्त मंत्री सीतारमन ने यह विश्वास जताया है कि, वर्ष 2022-23 में औसतन ग्रोथ रेट 7.4 प्रतिशत रहेगी तथा अगले वर्ष में इतनी ही रहेगी।**
- **सोसायटी जनरल के जाने-माने अर्थशास्त्री कुनाल कुण्डू के अनुसार, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इतनी नहीं है कि, हर साल देश के लेबर फोर्स में जुड़ रहे एक करोड़ बीस लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।**
- **कुनाल कुण्डू का यह भी कहना है, सरकार ने पूंजी निवेशकों (इन्वैस्टरों) का सहारा लेकर ग्रोथ की रेट को गिरने से रोका तो है, पर बेरोजगारी के कारण डॉमैस्टिक कन्ज़म्पशन (खपत) उतनी नहीं बढ़ रही। अतः इसीलिये भारत की ग्रोथ रेट ''प्री-पैन्डैमिक'' स्तर तक नहीं पहुंची है।**

अक्टूबर-दिसम्बर की तिमाही में 4.5 प्रतिशत और नीचे गिरने से पूर्व आर्थिक वृद्धि में इस तिमाही में दूसरी तिमाही की 15.2 प्रतिशत की मध्यस्थ भविष्यवाणी की तुलना में 6.2 प्रतिशत वार्षिक गिरावट की संभावना है। इसकी गत वित्त वर्ष की इसी अवधि से भी तुलना की गई है।

एफ.आई.सी.सी.आई.-आर.बी.ए. सर्वे में बैंकर्स के इस विचार का रहस्योद्घाटन किया गया है कि इस वर्ष ओमक्रान लहर आने के बावजूद की गई खामोश शुरूआत के बावजूद भारत में आर्थिक गतिविधियां रिकवरी मोड पर है। आर्थिक विकास को विविधतापूर्ण अंदाज में देखा जा रहा है क्योंकि अधिकांश सैक्टर्स वैश्विक महामारी पूर्व के स्तरों पर चल रहे हैं। महामारी से सर्वाधिक प्रभावित सम्पर्क आधारित सर्विस सैक्टर में भी थोड़ा बहुत सुधार देखा जा रहा है।

22 से 26 अगस्त तक किए गए रॉयटर्स के एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022 में आर्थिक वृद्धि की मध्यम उम्मीद 7.2 प्रतिशत की थी, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने बताया कि इस मजबूत वृद्धि में यह बात भी अन्तर्निहित है कि अर्थव्यवस्था के आागमी महीनों में कितनी तेजी से नीचे गिरने की उम्मीद है।

तथापि, सीतारमण का कहना है कि भारत का ग्रोस डोमैस्टिक प्रोडक्ट (जी.डी.पी.) वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 में 7.4 फीसदी बढ़ेगा और अगले वित्त वर्ष में भी इसी स्तर पर रहेगा। उन्होंने शुक्रवार को कहा था कि ''घटनाक्रमों के आधार पर हमारे स्वयं के घटनाक्रमों ने दर्शाया है कि हम निश्चित रूप से 7.4 प्रतिशत की रेंज पर हैं और यह स्तर अगले वर्ष भी जारी रहेगा।''

सोसिएते जनरल में भारत के अर्थशास्त्री कुनाल कुण्डू के अनुसार ''भारत के सबसे तेज गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने के बावजूद घरेलू

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तृणमूल कांग्रेस को गुरूर हो गया था कि, उसे मिला भारी जनमत उसका कवच है

पर लगातार तृणमूल के महारथियों के पास मिली करोड़ों की सम्पत्ति व धन ने इस गुरूर को चकनाचूर कर दिया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 अगस्त। जैसे-जैसे तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेताओं द्वारा संचित की गई अपार सम्पत्ति की नई-नई जानकारियाँ सामने आती जा रही हैं, वैसे-वैसे तृणमूल कांग्रेस तथा ममता बनर्जी पर खासकर फन्दा कसता जा रहा है।

सी.बी.आई. ने ममता बनर्जी के भतीजे तथा तणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को इसी शुक्रवार को तलब किया है। यह जाँच एजेन्सी अवैध कोयला-सौदों में उनकी लिप्तता की जाँच करना चाहती हैं।

- **अनुब्रत मण्डल व उनके रिश्तेदारों के पास बंगाल में 162 प्रॉपर्टी होना पाया गया है। उनकी पुत्री के पास 16 सम्पत्ति पायी गयीं, इनमें से कुछ कोलकाता के संभ्रान्त धनाढ्य इलाकों में हैं, बाकी अन्य जिलों में फैली हैं। परिवार के पास घोषित आय के कोई ऐसे स्रोत नहीं हैं, जो इन सम्पत्तियों का होना जायज साबित कर सकें।**
- **सी.बी.आई. ने अब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को भी समन करके पूछताछ के लिये बुलाया है। उन पर करोड़ों रूपये के सौदे करने का आरोप है, कोयले की खरीद-बिक्री के लिये।**
- **ममता बनर्जी ने बहुत भावुक होकर प्रेस के सामने कहा कि, अब आरोप लगाया जा रहा है कि, कोयले के सौदों का पैसा उनके निवास ''कालीघाट'' में पहुंच गया है।**
- **हर रोज एक नया घोटाला सामने आने से ममता बनर्जी, हतप्रभ सी हैं और बच निकलने का रास्ता ढूंढ रही हैं।**

कोयला-घोटाले तथा इससे जुड़ी बहुत बड़ी धनराशि के आरोप कुछ समय से चर्चा में हैं। इन साधनों के साथ ही, सी.बी.आई. सीधे ही ममता बनर्जी के परिवार में प्रवेश कर गई है। आज प्रैस को भावनात्मक लहजे में संबोधित करते हुये, ममता बनर्जी ने इन आरोपों का जिक्र किया तथा संबंधित संदेहों को हल्का करने की कोशिश की।

ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है कि अवैध कोयला-सौदों से कमाया गया पैसा ''काली घाट'' पहुँचा है। ''काली घाट'' शब्द का प्रयोग प्राय: सुश्री ममता बनर्जी के आवास के लिये किया जाता रहता है। ममता बनर्जी अपने भतीजे की तरह ही, कोलकाता के काली घाट क्षेत्र में रहती है। इसके साथ, तृणमूल कांग्रेस के अनेक नेताओं के पास आय से ज्यादा सम्पत्ति होने के दैनिक खुलासे पार्टी के निर्दोष होने के दावों को खोखला साबित कर रहे हैं। अब यह सुपुष्ट हो गया है कि अनुव्रत मण्डल तथा उसके नजदीकी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दालें 8 रू. किलो

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 अगस्त। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने बुधवार को निर्णय लिया है कि 15 लाख टन दाल, जिनमें चना, तुअर, उड़द तथा मसूर की दालें शामिल हैं, सभी राज्यों को 8 रु. प्रति किलो की डिसकाउन्ट कीमत पर ''पहले आओ-पहले पाओ'' के आधार

- **प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ने राज्यों के लिए 15 लाख टन दालों का कोटा जारी किया है तथा ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर 8 रू. प्रति किलोग्राम की दर से राज्यों को दालें दी जाएंगी।**

पर दी जायेंगी।

12 माह के लिये वितरित की जाने वाली दालें केवल एक बार ही या पूरी 15 लाख टन दालों के वितरण होने तक दी जायेंगी। इससे केन्द्र पर 1200 करोड़

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

के.सी.आर. बिहार में और केजरीवाल चेन्नई में

आखिर विपक्ष की हाण्डी में क्या पक रहा है?

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 अगस्त। आज दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव (के.सी.आर.) अगर बिहार में हैं तो शिक्षक दिवस अर्थात 5 सितम्बर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल चेन्नई में होगा कि उनकी चेन्नई यात्रा कुछ सरकारी तो कुछ राजनैतिक होगी। ज्ञातव्य है कि केन्द्र सरकार एवं भाजपा के साथ केजरीवाल की लड़ाई चलती ही रहती है।

तमिलनाडू के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के आमंत्रण पर वहां जा रहे केजरीवाल, स्टालिन के साथ संयुक्त रूप से तमिलनाडू सरकार के उन नये शैक्षिक प्रोजैक्टों का उद्घाटन करेंगे, जो दिल्ली सरकार द्वारा संचालित इसी प्रकार के प्रोजैक्टों से प्रेरित होकर बनाए गये हैं।

स्टालिन द्वारा केजरीवाल को महत्व दिये जाने के उनके कदम में निहित प्रतीकात्मकता किसी से छिपी हुई नहीं है क्योंकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर केन्द्र सरकार तथा भाजपा के हमले और अधिक तेज हो गये हैं तथा केजरीवाल सरकार को अस्थिर करने तथा गिराने की अटकले भी लगाई जा रही हैं। राजनैतिक रूप से, स्टालिन भी तमिलनाडू में भाजपा की आक्रामकता का सामना कर ही रहे हैं। लेकिन स्टालिन और डी.एम.के.-दोनों की ही किस्मत अच्छी है कि तमिलनाडू की मुख्य विपक्षी पार्टी ए.आई.ए.डी.एम.के. अर्थात अन्नाद्रमुक अपनी अंदरूनी लड़ाई में फंसी हुई है तथा और पहले ही टूट चुकी है। इसलिये, वे किसी बड़ी लड़ाई से बचे हुये हैं।

स्टालिन की शासन व्यवस्था तथा सरकारी योजनाओं की क्रियान्विति एवं नीति-निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन के लिये एक सक्षम टीम के गठन को लेकर उनके धुर विरोधी भी चकित हैं। वे ऐसे

- **केजरीवाल को आमंत्रित करने, स्टालिन सरकार के शिक्षा मंत्री स्वयं आये थे।**
- **आगामी शिक्षक दिवस पर, स्टालिन व केजरीवाल तमिलनाडू में, दिल्ली की तर्ज पर छात्राओं के लिये स्थापित 26 स्कूल ऑफ एक्सलैंस व 15 मॉडल स्कूलों के प्रोजैक्ट का शुभारंभ करेंगे।**
- **जैसा कि एक अनुभवी राजनीतिक नेता ने टिप्पणी की, जब दो राजनीतिक नेता मिल बैठकर बात करेंगे तो राजनीतिक स्थिति का मंथन तो होगा ही।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोनिया गांधी को मातृ शोक

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 अगस्त। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की माँ, श्रीमती पाओला माइनो का 27 अगस्त को, इटली में उनके घर पर देहान्त हो गया। मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया।

- **सोनिया गांधी की मां पाओला मैनो का 27 अगस्त को इटली में देहान्त हो गया, मंगलवार को उनका क्रियाकर्म किया गया।**

कांग्रेस महासचिव तथा मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्विट्र पर यह खबर साझा की। तथापि, उन्होंने यह नहीं बताया कि, सोनिया गांधी अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल हो पाईं या नहीं। सोनिया गांधी, अपने पुत्र राहुल गांधी व पुत्री प्रियंका गांधी वाडरा के साथ 23 अगस्त को अमेरिका में अपने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'चाहे मैं हूं या कोई भी, पार्टी का निर्देश सबने माना है, आगे भी आलाकमान जो बोलेगा, वह सभी को मानना होगा'

पायलट ने कहा, राजनीति में जो होता है वह दिखता नहीं और जो दिखता है वह होता नहीं

जयपुर, 31 अगस्त (का.प्र.)। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चल रही चर्चाओं पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि, राजनीति में जो होता है वह दिखता नहीं और जो दिखता है वह होता नहीं। ऐसे में इस मामले में जो अफवाहें चल रही हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं देता। चाहे मैं खुद हूं या राजस्थान का कोई भी नेता हो, हमें पार्टी से जो भी निर्देश मिले उनको हमने पहले भी माना है और आगे भी मानेंगे। यह बात कह कर पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से लगातार कही जा रही उन बातों पर कटाक्ष किया है, जिनमें मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि वे राजस्थान में ही रहेंगे और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की उनकी चर्चा मात्र मीडिया की ओर से कही जा रही है।

पायलट ने कहा कि, जो खबरें चल रही हैं, उन पर हम ध्यान नहीं देते। ऐसे में अफवाहों पर जाने के बजाय, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इसे लेकर इंतजार करना चाहिए। सारा चुनाव घोषित हो चुका है और 22 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और रिजल्ट सामने आ जाएगा कि कौन अध्यक्ष होगा। लेकिन हम सब जो पार्टी में हैं, चाहे मैं हूं या कोई भी, जो पार्टी का निर्देश हुआ है हम सबने लगन और ईमानदारी से उसकी पालना की है। राजस्थान के सभी नेता यह बात बोल चुके हैं कि, जो आलाकमान बोलेगा, वो हम करेंगे।

पायलट ने अपने बयान के जरिए साफ किया है कि, उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के कहने पर राजस्थान में 2018 में सरकार बनने पर उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया था। ऐसे में आगे अगर किसी भी नेता को आलाकमान से कोई भी निर्देश मिलते हैं तो उसे वह निर्देश मानने ही होंगे।

- **उन्होंने कहा, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के खिलाफ राजस्थान में हो रहे अत्याचार के मामले चिंताजनक हैं, एस.सी. आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए।**
- **पायलट ने आगे कहा, ऐसा बहुत सालों में पहली बार हुआ कि एन.एस.यू.आई. सभी युनिवर्सिटी में चुनाव हार गई, हम लोगों को चिंता करनी चाहिए कि कमी कहां रह गई।**

एक सवाल के जवाब में पायलट ने, नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं पर चिंता जताते हुए महिलाओं के साथ ही प्रदेश में दलितों, आदिवासियों के साथ बढ़ रहे अत्याचार को भी चिंताजनक बताया। पायलट ने राजस्थान एससी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग रखते हुए बढ़ते अपराध को रोकने के लिए कानून की सख्ती से पालना करवाने की बात कही।

पायलट ने कहा कि, न्याय लोगों को समय पर मिले यह बहुत जरूरी है, ताकि किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि गरीब, दलित पर अत्याचार करने की सोच सके। पायलट ने कहा, मैंने जालोर में भी कहा था कि कानून बनाने से लोगों के जेहन में डर नहीं बैठता। एक्शन के जरिए ऐसा वातावरण हमें बनाना होगा कि कोई भी व्यक्ति बच्चियों, दलितों और आदिवासियों पर इस तरह से आक्रमण करने की हिम्मत ना कर सके।

पायलट ने राजस्थान की सभी युनिवर्सिटी में एनएसयूआई को मिली हार पर कहा कि, ऐसा बहुत सालों में पहली बार हुआ है कि एनएसयूआई सभी युनिवर्सिटी में चुनाव हार जाए। इसे लेकर हम लोगों को चिंता करनी चाहिए कि, कमी कहां रह गई। क्या कैंडिडेट सिलेक्शन गलत हुआ या प्रचार में कमी रह गई या फिर सरकार की कामयाबी और सरकार के 4 साल के कार्यकाल को हम जनता के सामने लेकर नहीं गए। पायलट ने कहा कि, नौजवान प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, नौजवानों की भावना, सोच और जो उम्मीदें हैं उनको कैसे पूरा करना है, उस पर ध्यान देना चाहिए।

पायलट ने कहा कि, करीब 14 युनिवर्सिटी में चुनाव हुए हैं। उनमें हम जीत नहीं सके, इसलिए पार्टी को भी और हमारे संगठन को भी यह चिंता करनी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राडिया टेप्स

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 अगस्त। टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन एन. टाटा की 2010 की रिट याचिका, जिसमें उन्होंने राडिया टेप की मीडिया लीक के

- **टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा ने राडिया टेप्स प्रकरण में वर्ष 2010 में निजता की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि, केन्द्र सरकार 2012 में ही राडिया टेप्स को नष्ट कर चुकी है।**

परिणामस्वरूप, अपनी प्राइवेसी की सुरक्षा की मांग की थी, की सुनवाई गुरूवार को सर्वोच्च न्यायालय में होनी है, जबकि सरकार यह बात कह चुकी है

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)